

सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन

स्रोत: पी.आई.बी

भुवनेश्वर, ओडिशा में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन में नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को उजागर करना था।

- थीम: 'गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस' में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत पहलों को दर्शाया गया है।
- प्रमुख नवोन्मेषी डिजिटल उपकरण: सम्मेलन में **केंद्रीयकृत लोक शिकायत नविवरण एवं नगिरानी प्रणाली (CPGRAMS)** और **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र** (जिसी **जीवन प्रमाण** भी कहा जाता है) को प्रमुख रूप से उजागर किया गया, जो नवाचारयुक्त शासन के वैश्विक मॉडल के रूप में उभरे हैं।
- **CPGRAMS**: यह नागरिकों के लिये सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने हेतु 24x7 ऑनलाइन मंच है।
 - इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मंच सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों को आपस में जोड़ता है।
 - यदि समाधान असंतोषजनक हो, तो यह अपील करने की सुविधा भी प्रदान करता है। हालाँकि, यह मंच सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित प्रश्नों, न्यायालय या वचिराधीन मामलों, धार्मिक मुद्दों और सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शिकायतों को शामिल नहीं करता।
- **जीवन प्रमाण**: यह एक बायोमेट्रिक-सकषम डिजिटल सेवा है, जिसी वर्ष 2014 में पेंशनधारकों के लिये जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शुरू किया गया था। अब पेंशनधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय **मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** के माध्यम से अपनी पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित कर सकते हैं।
 - यह सेवा पेंशन का नरिंतर वितरण सुनिश्चित करती है और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करती है। यह केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी पेंशनधारकों के लिये उपलब्ध है।
 - वर्ष 2014 से अब तक जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से 10.31 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किये जा चुके हैं, जो पेंशनधारकों में इसकी व्यापक लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

और पढ़ें: [डिकोडिंग गुड गवर्नेंस](#)